RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 24 MAY TO 30 MAY 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 35 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

प्लास्टिक उद्योग से देश में पैदा होंगे रोजगार के 5 लाख अवसर, आत्मनिर्भर बनेगा भारत Page 2

भारत की GDP पहली बार 350 लाख करोड़ पार Page 4

रघुराम राजन ने दिया था रू. 10000 के नोट का छापने का आइडिया, क्यों हुआ था रिजेक्ट Page 5

editoria!

लोगों की उलझन दूर करें

दो हजार रुपये के नोटों की वापसी की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। अगर बैंकों से लंबी कतारें लगने या बेहिसाब भीड़ जमा हो जाने की खबरें नहीं आ रहीं तो इसकी एक वजह तो यही है कि इन नोटों का चलन काफी पहले से कम होता जा रहा था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2023 को सर्कुलेशन में मौजूद दो हजार के नोटों की संख्या कुल नोटों का 10.8 फीसदी ही रह गई थी। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि पिछली बार यानी 2016 में हुई नोटबंदी के विपरीत इस बार इन नोटों को लीगल टेंडर बनाए रखा गया है। इन्हें बदले जाने की समयसीमा भी ठीकठाक लंबी (30 सितंबर तक) रखी गई है। सोमवार को खुद आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी ये नोट मान्य होंगे और यह संकेत भी दिया कि जरूरत होने पर यह समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। बावजूद इसके, दो हजार के नोट वापस लिए जाने की घोषणा करंसी मैनेजमेंट के लिहाज से कोई अच्छी मिसाल नहीं कही जाएगी। भले ही आबादी का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इस फैसले से प्रभावित न हो रहा हो, लेकिन इसमें हर आम ओ खास के लिए सरप्राइज एलीमेंट जरूर है। इसने सबको न केवल एक बार चौंका दिया बल्कि उनके जेहन में दर्ज नोटबंदी के कड़वे अनुभव को फिर ताजा कर दिया। इसके अलावा नोटबंदी के मुकाबले ज्यादा सतर्कता और ज्यादा सहजता से अमल किए जाने के प्रयासों के बावजूद इस बार भी अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति टाली नहीं जा सकी। सोमवार को आए आरबीआई गवर्नर के स्पष्टीकरण के बाद भी अभी तक यह साफ नहीं है कि नोट बदलवाने के लिए बैंक जाने वालों को आईडी दिखाने और फॉर्म भरने की जरूरत होगी या नहीं। एसबीआई की घोषणा के मुताबिक इसकी जरूरत नहीं है लेकिन अलग-अलग बैंकों की ओर से बताया जा रहा है कि इसकी जरूरत होगी। यह भी तय नहीं है कि एक बार में अधिकतम 10 नोट बदलवाने की सीमा का क्या मतलब है। क्या यह सीमा एक दिन के लिए है या कतार में काउंटर पर आने वाली अपनी बारी से मतलब है। यानी क्या उसी समय दोबारा कतार में लगकर कोई चाहे तो दूसरी और फिर तीसरी बार भी 10-10 नोट बदलवा सकता है? इसके अलावा नोट वापसी की इस घोषणा ने यह विचित्र स्थिति पैदा कर दी है कि दो हजार के जो नोट देश की करंसी का हिस्सा हैं और आज भी लीगल टेंडर हैं, बाजार में स्वीकार नहीं किए जा रहे। इस स्थिति को निस्संदेह टाला जा सकता था। हालांकि यह बात रेखांकित किए जाने की जरूरत है कि अपने देश में करंसी की साख काफी अच्छी है। वरना डिजिटल ट्रांजिशन की इतनी तेज और सहज प्रक्रिया संभव नहीं थी। लेकिन हमारे नीति-निर्माताओं को पॉलिसी की स्थिरता से जुड़े सबकों पर शायद फिर से गौर करने की जरूरत है।

बैंकों में 2000 का नोट बदलवाते समय रहें सावधान

नकली निकला तो होगी FIR, जानिए क्या हैं नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, उन्होंने बैंक जाकर इन्हें बदलवाना शुरू कर दिया है। बैंक 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोटों को जमा करेंगे। दो हजार रुपये के इन नोटों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। आरबीआई और बैंक इन सवालों के जवाब पहले ही दे चुके हैं। आरबीआई ने कहा है कि दो हजार के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। लेकिन ये नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं। इसका मतलब है कि लोग इन नोटों से खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार में दो हजार रुपये के सिर्फ 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बदलवा सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये के नोट की नकल तैयार नहीं की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि कोई भी 2000 रुपये के सुरक्षा मानकों के स्तर का तोड़ नहीं निकाल पाया है। उन्होंने कहा, 'अभी केवल फाइन फोटोकॉपी ही 2000 रुपये के नकली नोटों के रूप में पाई गई है।'

नोटों की होगी जांच

कोई भी ग्राहक 2000 रुपये का नकली नोट जमा नहीं कर पाए, इसके लिए बैंकों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए नोटों की जांच की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अगर कोई नकली नोट पकड़ में आता है, तो उसे जब्त किया जाएगा और उस पर फेक करेंसी की मुहर लगा दी जाएगी।

नकली नोट जमा किया तो जाएंगे जेल

अगर आपने बैंक में 2 हजार रुपये का नकली नोट जमा किया तो आपकी खैर नहीं है। उस नकली नोट को जब्त किया जाएगा और उसके बदले कोई नोट वापस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, किसी एक व्यक्ति के पास 5 से ज्यादा नकली नोट मिलते हैं, तो उस पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके बाद उस व्यक्ति पर जरूरी कानूनी कार्रवाई होगी।

सावधान रहें

बाजार में नकली नोट चलाने वाले अपराधी ऐसे मौकों पर सक्रिय हो जाते हैं। वे मौके का फायदा उठाने लगते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे इतने 2000 के नोट बदलवा दो और बदले में भारी कमीशन की पेशकश करे, तो सतर्क हो जाएं। ये नकली नोट भी हो सकते हैं।

मोदी राज में पहली बार 16 फीसदी गिरा एफडीआई, लगा बड़ा झटका

नई दिल्ली। एजेंसी

विदेशी निवेश के मामले में भारत को बड़ा झटका लगा है। मोदी राज में पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एफडीआई (FDI) में 16 फीसदी तक की गिरावट आई है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का पता चला है। रिजर्व बैंक के स्टेट ऑफ दी इकोनॉमी नाम के एक लेख में बताया गया है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान ग्रॉस इनवार्ड एफडीआई में 16 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। एफडीआई का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2021-22 में 84.8 बिलियन डॉलर रहा था। यह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 16.3 फीसदी कम होकर 71 बिलियन डॉलर रह गया है। यह पिछले एक दशक में पहली गिरावट है।

बढ़ सकता है विदेशी निवेश

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डीके जोशी के मुताबिक, भारत, जी -20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए संरचनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है। ऐसे में सरकार को ग्लोबल सप्लाई चेन में चल रहे डायवर्सिफिकेशन का फायदा उठाना चाहिए। भारत को और भारत के मैन्युफैक्चिरिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना चाहिए। बीते दिनों अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि 'निवेशक अनिश्चितता और जोखिम प्रतिकूलता वैश्विक एफडीआई पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकती है'। अगर नेट बेसिस पर देखें तो भी एफडीआई 27.5% घटकर 28 बिलियन डॉलर हो गया है। जनवरी में जारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में, चीन में एफडीआई का प्रवाह 8% बढ़कर 189 बिलियन डॉलर हो गया था। आंकड़ों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में एफडीआई में सबसे ज्यादा कमी आई है, उनमें विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाएं और संचार सेवाएं शामिल हैं। इस दौरान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और मॉरीशस से एफडीआई कम हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में नेट एफडीआई का आंकड़ा 38.6 बिलियन डॉलर रहा था, जो पिछले वित्त वर्ष में कम होकर 28 बिलियन डॉलर रह गया।

प्लास्टिक उद्योग से देश में पैदा होंगे रोजगार के 5 लाख अवसर, आत्मनिर्भर बनेगा भारत

नई दिल्ली। एजेंसी

आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ते हुए एआईपीएमए ने प्लास्टिक के सामान के आयात पर एक विस्तृत अध्ययन किया है। आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) ने देश में प्लास्टिक के सामान के आयात पर एक विस्तृत अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 37,500 करोड़ रुपये के प्लास्टिक के सामान का आयात किया गया। इसमें 48 फीसद सामान का आयात चीन से किया गया । विस्तृत विश्लेषण के बाद एआईपीएमए ने आयात पर निर्भरता कम करने और देश में प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से 550 प्लास्टिक उत्पाद का चयन किया है। इस अध्ययन के आधार पर अनुमान जताया गया है कि आयात निर्भरता के बजाय घरेलू स्तर पर 37,500 करोड़ रुपये के प्लास्टिक के सामान के उत्पादन के लिए हर साल देश में लगभग 4 मिलियन टन कच्चे माल और 16,000 से अधिक प्लास्टिक प्रॉसेसिंग मशीनों की आवश्यकता होगी, जिसमें उपकरण, मोल्ड्स, जिग्स और फिक्स्चर शामिल हैं। इससे देश में 5 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को एआईपीएमए के अध्यक्ष मयूर डी. शाह और एआईपीएमए की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद मेहता ने संबोधित किया । मयूर डी शाह ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग देश में सालाना 3.5 लाख करोड़ रुपये के सामान का निर्माण करता है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका प्रमुख योगदान है। उन्होंने कहा कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत दुनिया का प्रीमियम सप्लाई हब बन सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय प्लास्टिक उद्योग इस समय देश में 5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इसकी 50,000 प्रॉसेसिंग यूनिट्स हैं, जिनमें 90 फीसदी छोटे और मध्यम उद्यमों से संबंधित हैं। यह प्लास्टिक उद्योग भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में अहम भूमिका निभाएगा।

प्लास्टिक के सामान के आयात पर निर्भरता कम करने और देश में प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से एआईपीएमए छह प्रौद्योगिकी सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। इन सम्मेलनों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के सामान के आयात पर निर्भरता को कम करना और 'मेक इन इंडिया - मेक फॉर द वर्ल्ड' के तहत घरेलू उद्योगों को प्लास्टिक के सामान के उत्पादन में मदद मुहैया कराना है।

रूस ने भारत को दी तेल और हथियारों की डील कैंसिल करने की धमकी, जानिए क्या है सारा माजरा

मॉस्को। एजेंसी

भारत और रूस के संबंध दोनों देशों की विदेश नीति का एक अहम स्तंभ है। भारत हमेशा से रूस को एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर देखता आ रहा है। लेकिन अब ये रिश्ते बदल रहे हैं। एक रिपोर्ट की मानें तो रूस ने भारत को ऊर्जा और हथियारों की डील कैंसिल करने की धमकी दी है। जून तक रूस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ब्लैकलिस्ट में आ सकता है। इस लिस्ट में आने से बचने के लिए रूस ने भारत से मदद की मांग की है। मदद ने करने पर या इसमें असफल रहने पर उसने भारत को डील रद्द करने की धमकी दे डाली है।

रूस ने मांगी मदद

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग-थलग पड़े रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। एफएटीएफ की तरफ से पड़ा दबाव अब रूस की धमकी के रूप में सामने आ रहा है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों की फाइनेंसिंग पर बैन लगाने वाला संगठन है। जून में इसकी एक मीटिंग होनी है जिसमें रूस पर प्रतिबंध पर फैसला हो सकता है। भारत इसका सदस्य है और फरवरी 2022 में जब यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई तो एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता खत्म कर दी थी। अब ऐसे में वह उन देशों से मदद मांग रहा है जो उसे ब्लैकलिस्ट होने से बचा सकें।

पहले ही प्रतिबंध झेल रहा रूस

यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही रूस पर काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर ऐसे में एफएटीएफ की तरफ से इसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो फिर रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार की ही श्रेणी में आ जाएगा। अगर रूस ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर एफएटीएफ के सदस्य, बैंक, निवेश कंपनियां और पेमेंट सिस्टम को सावधानी बरतनी होगी। यहां तक कि इनके पास रूस पर जवाबी कार्रवाई का भी अधिकार होगा। युद्ध के बाद से ही प्रतिबंधों को झेलने वाला रूस अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया तो फिर बची-खुची अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। ऐसे में एफएटीएफ की लिस्ट में आना उसकी मुसीबतों को डबल करने वाला कदम होगा।

अगर ब्लैकलिस्ट हुआ तो...

रूस ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर वह ब्लैकलिस्ट हुआ तो फिर दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और बाकी डील खतरे में आ जाएंगी। जिन डील्स को लेकर रूस ने धमकी दी है उनमें हथियारों का निर्यात, तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और नायरा एनर्जी लिमिटेड के बीच सहयोग और रेलवे कॉरिडोर का विकास शामिल है। रूस, भारत का टॉप हथियार सप्लायर रहा है। पिछले साल वह तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी सामने आया है। रूस ने यह भी कहा है कि एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में आना भले ही एक कम गंभीर फैसला हो लेकिन इससे डील पर खतरा रहेगा।

रुपया 15 पैसे की बढ़त के साथ 82.70 प्रति डॉलर पर

नई दिल्ली। एजेंसी

विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ने के कारण अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 15 पैसे की तेजी के साथ 82.70 (अस्थायी) प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। बाजार सूत्रों ने कहा कि अपनी प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने तथा कमजोर घरेलू शेयर बाजार के कारण रुपये का लाभ सीमित रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.83 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के अंत में यह अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 15 पैसे की तेजी के साथ 82.70 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रुपया 82.64 के उच्चस्तर तक गया और 82.84 के निचले स्तर तक आया। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 82.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.18 प्रतिशत बढ़कर 103.67 हो गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 208.01 अंक की गिरावट के साथ 61,773.78 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.81 प्रतिशत बढ़कर 78.23 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयरखान बाय बीएनपी परिबा के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि डॉलर के कमजोर रहने तथा विदेशी संस्थागत निवेश बढ़ने से रुपये में तेजी आई। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने मंगलवार को 182.51 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

दुकानदार बिल देने के लिए नहीं मांग सकेंगे आपका मोबाइल नंबर

सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

दुकान पर आप जब भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार बिल (ँग्त) देने से पहले आपसे मोबाइल नंबर जरूर मांगते हैं। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद दुकानदार आपको बिल देते हैं। लेकिन अब जल्द ही आपको बिल पाने के लिए मोबाइल नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इस चलन को खत्म करने के लिए सलाह जारी करने वाला है। दरअसल बिल (ँग्त) देने से पहले हर बार मोबाइल नंबर मांगे जाने के चलन पर लोग लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के मुताबिक, केंद्र कई शिकायतों के मिलने के बाद अब एडवाइजरी जारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राहक के मोबाइल नंबर पर जोर देने वाला कोई भी सेलर 'अनुचित व्यापार व्यवहार' के तहत आता है। ग्राहकों ने कई खुदरा विक्रेताओं के बारे में शिकायत की है कि अगर वे अपना मोबाइल नंबर देने से मना करते हैं तो वे उन्हें सर्विस उपलब्ध नहीं कराते हैं। इधर 'विक्रेताओं का कहना है कि वे मोबाइल नंबर दिए जाने तक बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत यह एक अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार चलन है। इस जानकारी को एकत्र करने के पीछे कोई तर्कसंगतता नहीं है। जब तक ग्राहकों की सहमति न हो, उन्हें नंबर नहीं लेना चाहिए।

मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं

भारत में ग्राहकों के लिए खरीदारी करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर समय उन्हें मोबाइल नंबर देना पड़ जाता है। अधिकारियों के मुताबिक, यह भी निजता की चिंता है और ग्राहक के पास यह अधिकार है कि वह अपना मोबाइल नंबर शेयर करे या नहीं करे। उन्होंने कहा कि सेल्सपर्सन द्वारा ग्राहकों को सूचित करने की शिकायतें हैं कि वे बिना संपर्क नंबर के बिल नहीं बना सकते क्योंकि यह सिस्टम में इनबिल्ट है।

जोर देकर नहीं मांग सकते नंबर

अधिकारियों के मुताबिक, वह विक्रेताओं को इस बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश देंगे कि अगर कोई ग्राहक सामान खरीदने के बाद बिल के लिए अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता है तो सेल्सपर्सन को इसपर जोर नहीं देना चाहिए। उपभोक्ताओं के हित में इस मुद्दे को हल करने के लिए खुदरा उद्योग और CII, FICCI और ASSOCHAM जैसी संस्थाओं को सलाह भेजी जाएगी। एक अन्य कदम में, मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को स्मार्ट फोन, लैपटॉप और टैबलेट के लिए यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट - यूएसबी टाइप-सी - पेश करने पर अपने विचार भेजे हैं, जिसमें सुझाव दिया गया है कि इन चार्जर का रोलआउट जून 2025 से किया जा सकता है। दरअसल मंत्रालय ई-कचरे को कम करने के लिए केवल दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग उपकरणों के लिए सामान्य चार्जर के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है।

भारत की GDP ग्रोथ FY23 में 7% से ज्यादा रहेगी, RBI गवर्नर ने दिया भरोसा

Indian GDP: दुनिया भर के देश आर्थिक सुस्ती से डरे हुए हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत ग्रोथ दिखा सकती है। यह कहना है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का । शक्तिकांत दास ने कहा कि, फिस्कल ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ 7 फीसदी से ज्यादा रह सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 24 मई को ण्ष्ठ के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। दास ने कहा, 'हाल के सभी ट्रेंड के मुताबिक, फिस्कल ईयर 2023 की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी से ज्यादा रहती है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान कर चलते हैं कि फिस्कल ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ 7 फीसदी रह सकती है । 'स्टैटिक्स मिनिस्ट्री ने GDP ग्रोथ पर अपना दूसरा पूर्वानुमान 28 फरवरी को जारी किया था। तब भारत की GDP ग्रोथ फिस्कल ईयर 2023 में 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया था।मिनिस्ट्री अब 31 मई को फिस्कल ईयर 2023 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2023) के लिए पहला प्रोविजनल अनुमान जारी करेगा। स्टैटिक्स मिनिस्ट्री के 7 फीसदी ग्रोथ के पूर्वानुमान को आधार बना लें तो जनवरी-मार्च 2023 तिमाही में उअ्ङ की ग्रोथ 5.1 फीसदी रह सकती है।

साल 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंची भारतीय अर्थव्यवस्था

नौकरशाही की लेटलतीफी बड़ा चैलेंजः मूडीज

नयी दिल्ली। एजेंसी

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को कहा कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) साल 2022 में 3,500 अरब डॉलर से अधिक रहा और अगले पांच वर्षों तक यह जी20 समूह में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने एक शोध रिपोर्ट में भारत की वृद्धि रफ्तार को लेकर आशावादी नजरिया जताने के साथ निर्णय-प्रक्रिया में शामिल नौकरशाही के रुख को लेकर आशंका भी जताई है। उसने कहा कि नौकरशाही का लेटलतीफी वाला रवैया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) गंतव्य के तौर पर भारत के आकर्षण को कम कर सकता है। सबसे कम कीमत पर बेहतरीन स्क्रीन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट लें। मूडीज के मुताबिक, भारत की वृद्धि रफ्तार पर नौकरशाही की तरफ से लगाई जाने वाली अड़चनें लगाम लगा सकती हैं। लाइसेंस लेने और कारोबार शुरू करने की अनुमति प्रक्रिया में नौकरशाही की धीमी रफ्तार परियोजनाओं की स्थापना के समय को बढ़ा सकती है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने रिपोर्ट में कहा कि निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में शामिल भारत की शीर्ष नौकरशाही इस क्षेत्र के इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले एक एफडीआई गंतव्य के तौर पर भारत के आकर्षण को घटा देगी। हालांकि, भारत की एक बड़ी युवा एवं शिक्षित श्रमशक्ति, छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या और शहरीकरण से आवास, सीमेंट एवं नई कारों के लिए मांग बढ़ेगी। इसके अलावा ढांचागत क्षेत्र पर सरकारी खर्च बढ़ने से इस्पात एवं सीमेंट कारोबार और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन से नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, विनिर्माण एवं ढांचागत क्षेत्रों में मांग इस दशक के बाकी समय में भारतीय अर्थव्यवस्था सालाना 3-12 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इसके बावजूद भारत की क्षमता वर्ष 2030 तक चीन से पीछे ही रहेगी। मूडीज ने कहा कि क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को लेकर भारत के सीमित उदार रवैये का भी विदेशी निवेश आकर्षित करने पर असर पड़ेगा। हालांकि, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने और कर संग्रह एवं प्रशासन को बेहतर करने के सरकारी प्रयास उत्साहजनक हैं लेकिन इन कोशिशों की प्रभाव को लेकर जोखिम भी बढ़े हैं।

डिफॉल्टर बनने के करीब सुपरपावर अमेरिका

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका में डेट सीलिंग का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो देश अपने इतिहास में पहली बार डिफॉल्टर बन सकता है। देश के पास अब केवल 57 अरब डॉलर का कैश रह गया है जो गौतम अडानी की नेटवर्थ से भी कम है। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 64.2 अरब डॉलर है। अमेरिका को रोजाना 1.3 अरब डॉलर इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ रहे हैं। देश में अब इस संकट का असर दिखने लगा है। मंगलवार को पहली बार अमेरिकी शेयर बाजार ने इस संकट पर रिएक्ट किया और चार घंटे में 400 अरब डॉलर स्वाहा हो गए। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चेतावनी दी है कि अगर इस संकट का समाधान नहीं किया गया तो एक जून को देश डिफॉल्टर बन जाएगा। जैसे-जैसे यह डेडलाइन करीब आ रही है, बाजार में गिरावट आ रही है और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है।

अमेरिका की उधार लेने की क्षमता को इसकी सुपरपावर माना जाता है। अगर वह पहली बार ऐसा नहीं कर पाता है तो इससे उसकी इमेज पर असर होगा। दुनियाभर में निवेश के लिए अमेरिका को सबसे बेहतर जगह माना जाता है। अमेरिका सरकार की तरफ से हमेशा कर्ज की मांग रहती है। इससे ब्याज दरें कम रहती हैं और यह डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाता है। अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स दुनियाभर में सबसे आकर्षक माने जाते हैं। इस कारण अमेरिका की सरकार डिफेंस से लेकर, स्कूल, रोड, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और साइंस पर दिल खोलकर खर्च करती है। अगर अमेरिका ने कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया तो सभी आउटस्टेंडिंग सीरीज ऑफ बॉन्ड्स प्रभावित होंगे। इनमें ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में जारी किए गए बॉन्ड्स, गवर्नमेंट टु गवर्नमेंट क्रेडिट, कमर्शियल बैंकों और इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स का साथ हुए फॉरेन करेंसी डिनॉमिनेटेड लोन एग्रीमेंट शामिल है।

अमेरिका ने डिफॉल्ट किया तो

अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो इसके भयावह नतीजे होंगे। व्हाइट हाउस के इकनॉमिस्ट्स का कहना है कि इससे देश में 83 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट आधा साफ हो जाएगा, जीडीपी 6.1 परसेंट गिर जाएगी और बेरोजगारी की दर पांच फीसदी बढ़ जाएगी। देश में इंटरेस्ट रेट 2006 के बाद टॉप पर पहुंच गया है, बैंकिंग संकट लगातार गहरा रहा है और डॉलर की हालत पतली हो रही है। देश में मंदी आने की आशंका 65 फीसदी है। अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो उसका मंदी में फंसना तय है। इसका पूरी दुनिया पर असर देखने को मिल सकता है। डेट लिमिट वह सीमा होती है जहां तक फेडरल गवर्नमेंट उधार ले सकती है। 1960 से इस लिमिट को 78 बार बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार इसे दिसंबर 2021 में बढ़ाकर 31.4 ट्रिलियन डॉलर किया गया था। लेकिन यह इस सीमा के पार चला गया है। White House Council of Economic Advisers के एक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई तो देश में कयामत आ जाएगी। इकॉनमी को भारी नुकसान होगा। जॉब ग्रोथ में अभी जो तेजी दिख रही है, वह पटरी से उतर जाएगी। लाखों रोजगार खत्म हो जाएंगे।

भारत की GDP पहली बार 350 लाख करोड़ पार

अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। एजेंसी

बीते कैलेंडर ईयर यानी 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पहली बार 3.5 लाख करोड़ डॉलर (350 लाख करोड़) से ऊपर निकल गया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को कहा कि भारत अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जी-20 अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन इसके लिए कुछ सुधारों की जरूरत होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में भारतीय GDP 3.18 लाख करोड़ डॉलर यानी 263.50 लाख करोड़ रुपए की थी। बहरहाल, मूडीज ने एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि ब्यूरोक्रेसी विभिन्न लाइसेंस लेने और बिजनेस स्थापित करने की प्रक्रिया धीमी कर सकती है। इसे प्रोजेक्ट की अवधि और लागत बढ़ा सकती है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा, 'निर्णय लेने में लेट लतीफी की वजह से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की रफ्तार कम कर देगी। खास तौर तब, जब एशिया-प्रशांत की अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, मसलन इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ भारत तगड़ी प्रतिस्पर्धा में है।'

मकान, सीमेंट और कार की डिमांड बढ़ाएगा तेज शहरीकरण

मूडीज के मुताबिक, भारत में बड़ी और पढ़ी लिखी वर्कफोर्स है। ऐसे में छोटे परिवार बढ़ेंगे। साथ ही तेज शहरीकरण से घर, सीमेंट और कार की डिमांड बढ़ेगी। मूडीज के मुताबिक, भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च स्टील और सीमेंट सेक्टर्स के लिए मददगार होगा, जबकि नेट-जीरो एमिशन हासिल करने की चाहत अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देगी। मूडीज ने ये भी कहा कि इन सेक्टरों में भारत की क्षमता 2030 तक चीन से कम रहेगी।

GDP क्या है?

GDP इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। उअ्ह देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है, तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है।

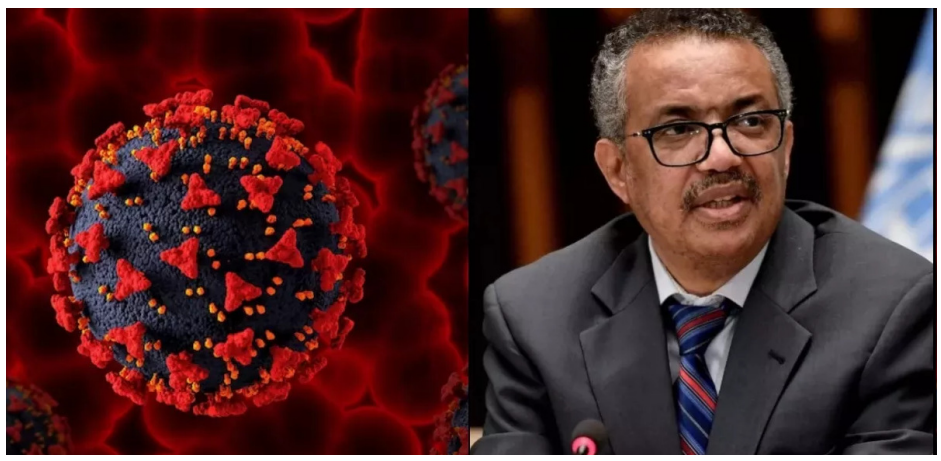

'दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए...'

आने वाला है कोरोना से भी खतरनाक वायरस, WHO ने दी चेतावनी

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इससे पहले एक और महामारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कोविड-19 महामारी से भी अधिक घातक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिकेंष्ठ प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने कहा कि दुनिया को एक ऐसे वायरस के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कोविड से भी घातक है। रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कम से कम 20 मिलियन लोग मारे गए हैं। बता दें कि हाल ही मेंेंष्ठ ने ऐलान किया था कि कोविड-19 महामारी अब हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। टेड्रोस ने स्विटजरलैंड के जिनेवा में हेल्थ मीटिंग में बताया कि यह अगली महामारी को रोकने के लिए बातचीत करने का समय है। WHO प्रमुख ने चेतावनी दी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका एक और प्रकार से उभरने का खतरा बना हुआ है, जो बीमारी और मौत का कारण बनेगा. WHO प्रमुख ने कहा कि जब अगली महामारी दस्तक दे रही है और जब पता है कि वह आएगी, तो हमें निर्णायक, सामूहिक और समान रूप से जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉ. टेड्रोस ने कहा कि इस पीढ़ी में महामारी से समझौता नहीं करने की प्रतिबद्धता है। क्योंकि यह वह लोग हैं, जिसने अनुभव किया कि एक छोटा सा वायरस कितना भयानक हो सकता है।

एफोटेल इंदौर के इंदौरी अड्डा में स्वादिष्ट खानपान

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

द क्यूब रेस्टोरेंट में, एफोटेल इंदौर द्वारा आयोजित इंदौरी अड्डा के आकर्षक माहौल में दुनिया भर में मशहूर इंदौरी भोजन और उसकी विशिष्ट व्यंजनों का अनुभव करें। 12 से 28 मई 2023 तक सराफा बाजार और छप्पन के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। इंदौरा अड्डा में उपलब्ध विभिन्न तरह के स्ट्रीट फूड व्यंजन, मनमोहक चाट, ताज़गी देने वाले पेय पदार्थ और मिठाइयाँ आपको संतुष्टि प्रदान करेंगी। इंदौर और मध्य भारत के सबसे लोकप्रिय व्यंजन जैसे पोहा-जलेबी, भुट्टे की खीस, दही वड़ा, खट्टा समोसा, दाल बाफला, जलेबा, खोपरा पेटीस, गराडू, मालपुआ, मावा बाटी आदि का स्वाद लें। एफोटेल इंदौर के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस श्री अनुराग आनंद ने बताया कि 'इंदौरी अड्डा के अद्भुत मेनू में इस क्षेत्र के अब तक के सबसे अच्छे व्यंजन शामिल किए गए हैं। ये व्यंजन इंदौरियों के लज़ीज़ खानपान के प्रति जुनून का प्रमाण हैं।' शानदार और आकर्षक मल्टी-कुज़ीन रेस्टोरेंट, द क्यूब के मेनू में देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजन शामिल हैं। मेहमानों के लिए तीनों वक्त के भोजन के लिए लोकप्रिय दक्षिण-भारतीय, पश्चिमी और एशियाई व्यंजनों की विस्तृत रेंज उपलब्ध है, जिनमें से वे अपना पसंदीदा व्यंजन चुन सकते हैं।

रघुराम राजन ने दिया था रू. 10000 के नोट का छापने का आइडिया, क्यों हुआ था रिजेक्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से एक नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है। 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट (2000 Notes) को बंद करने का फैसला लिया गया। आरबीआई के साल 2016 में नोटबंदी के बाद जिस नोट को जारी किया था, उसे करीब 8 सालों में ही वापस ले लिया। 2000 का नोट वापस लेने के फैसले के पीछे आरबीआई बार-बार दलील दे रहा है कि हाई वैल्यू वाले नोटों को बाजार से वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने दलील दी कि 2 हजार के बड़े नोट की बाजार में जरूरत नहीं है।

10 हजार रुपये के नोट छापने की सिफारिश

आपको जानकर हैरानी होगी आरबीआई ने जिन 2000 रुपये के नोट को ये कहकर वापस लेने का फैसला लिया कि बड़े नोट की जरूरत नहीं है, कुछ साल पहले उसी आरबीआई ने 5000 रुपये और 10000 रुपये के बड़े नोट को छापने की सिफारिश की थी। अक्टूबर 2014 में RBI के गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र सरकार को 5 हजार और 10 हजार रुपए के नोट जारी करने का सुझाव दिया था। रघुराम राजन ने इसके पीछे दलील दी थी कि देश में बढ़ती महंगाई के चलते 1 हजार रुपए के नोट की कीमत कम हुई है। बेकाबू महंगाई पर काबू पाने के लिए उन्होंने बड़े नोट को छापने की सिफारिश की गई।

अरुण जेटली ने कर दिया था इनकार

सेंट्रल बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार को 5 हजार और 10 हजार के नोट छापने की सलाह दी थी। आरबीआई गवर्नर के इस सुझाव को सरकार ने मानने से इंकार कर दिया है। उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया क्योंकि वह रीप्लेसमेंट करंसी जल्द चाहती थी, इसलिए सरकार ने 2 हजार रुपए के नोट जारी करने का फैसला लिया गया। हालांकि बाद में साल 2015 में रघुराम राजन ने खुद कहा था कि बड़े मूल्यवर्ग के नोटों के साथ जालसाजी का डर रहता है। जिसके चलते इसे रखना मुश्किल होता है। बड़े नोटों के साथ काला बाजारी आसान हो जाती है। भारत के पड़ोसी देशों से नकदी नोटों की जालसाजी आसान हो जाती है।

2000 ही नहीं, 5 और 10 हजार के नोट भी हुए बंद

कब और क्यों उठाना पड़ा था आरबीआई को ये कदम

एजेंसी

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी नोट को चलन से बाहर कर दिया गया हो। 2016 में तो 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध ही लगा दिया गया था। हालांकि, नोट को चलन से बाहर करने या फिर उस पर प्रतिबंध लगाने की कहानी 5-10 साल नहीं 75 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तब जब 10,000 के नोट भी छापे जाते थे। उस समय भी आरबीआई ने काले धन पर चोट की बात कहकर 10,000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। सबसे पहले यह काम 1946 में हुआ था. यानी आजादी से एक साल पहले।

मौजूद जानकारी के अनुसार, 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड ने बड़े नोटों के विमुद्रीकरण का अध्यादेश पारित किया था। इसके अगले दिन यानी 13 जनवरी 1946 को

500, 1000 और 10,000 के नोट चलन से बाहर हो गये थे। तब 100 रुपये से ऊपर के सभी नोट को बंद कर दिया गया था। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि कई बड़े व्यापारियों ने बड़े नोटों के रूप में काला धन जमा कर लिया था और इनकम टैक्स नहीं भर रहे थे। गौरतलब है कि भारत में अब तक 10,000 रुपये से अधिक के मूल्य वर्ग का कोई नोट नहीं छापा गया है।

1978 में फिर से नोटबंदी

1946 में बड़े नोट बंद हुए लेकिन 1954 में इन्हें फिर छापा गया। इस बार 10,000 रुपये के साथ 5,000 रुपये का भी नोट छपा। हालांकि, 1978 में मोरारदी देसाई के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक बार फिर नोटबंदी का ऐलान किया गया। 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट बंद कर दिये गए। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि सरकार पिछली सरकारों के कुछ भ्रष्ट नेताओं को निशाने पर ले रही थी।

2016 की नोटबंदी

8 नवंबर 2016 तो इस लेख को पढ़ने वाले लगभग सभी लोगों को याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा कर दी। इसके बाद नई सीरीज के 500 के नोट जारी किए गए लेकिन 1000 के नोट वापस नहीं लौटे। उनकी जगह 2000 के नोट लाए गए।

2000 का नोट चलन से बाहर

19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोट भी चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी। फिलहाल देश में 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये के नोट चलन में हैं। हालांकि 2,000 के नोट भी अभी बाजार में चलेंगे क्योंकि इन्हें अवैध नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 1, 2 और 5 रुपये के नोट भी अभी मान्य हैं लेकिन इनका चलन बहुत कम है. साथ ही इनकी छपाई भी बंद हो चुकी है।

रोजगार दिवस पर युवाओं के लिए लगा सांसद रोजगार मेला- वाधवानी

खुले मन से कि युवाओं ने इस मेले की तारीफ, दिया सांसद को धन्यवाद

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सांसद प्रतिनिधि विशाल गिद्धवानी और भाजपा नेता संतोष वाधवानी ने बताया कि मई 2023 बुधवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक ग्रामीण हाट बाजार धक्कन वाला कुआ के पास इंदौर में सांसद रोजगार मेला आयोजित हुआ। जिसमें कई युवाओं को हाथों हाथ रोजगार का ऑफर दिया गया युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सांसद की इश्क अनूठी पहल की शुरुआत की गई लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी के अथक प्रयासों से एक दिवसीय सांसद रोजगार मेला आयोजित किया गया आयोजन में इंदौर शहर के अलावा अन्य शहर के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांसद प्रतिनिधि संतोष वाधवानी ने बताया कि मेले का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद को युवाओं की टोली ने धन्यवाद भी प्रेषित किया वही इस तरह के आयोजन युवा हित में करते रहने का आग्रह भी किया गया आयोजन में श्री संकल्प वर्मा श्री पवन शर्मा श्री सीटू छाबड़ा श्री कपिल जैन श्री कमल पूरी लघु भारतीय उद्योग के श्री दीपक भंडारी श्री विशाल गिद्धवानी भाजपा नेता श्री पवन कुकरेजा पार्षद श्रीमती कंचन गिद्धवानी सुश्री रोशनी शर्मा सुश्री संध्या यादव और कई राजनेता व अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सोने के पुराने गहने अब नहीं बेच पाएंगे आप! सरकार ने बदले गोल्ड बेचने के नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि जमापूंजी है। भारत में लोग सोने को आभूषण से ज्यादा निवेश के तौर पर देखते हैं। ऐसा निवेश को मुश्किल के वक्त में कभी भी काम आ सकता है। अगर कभी ऐसी आर्थिक परेशानी आई तो कुछ ही घंटों में घर की तिजोरी में बंद सोने के जेवर आपके लिए एक इमरजेंसी फंड के तौर पर तैयार हो जाता है। सोने के गहने बेचकर लोग मुश्किल से बच निकलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने सोने के गहने खरीदने से लेकर बेचने तक का नियम बदल दिया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबित 1 अप्रैल से सरकार ने सोने के गहने बेचने के लिए भी हॉलमार्क यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब सोना बेचने के लिए भी हॉलमार्किंग जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार ने अब पुराने सोने के गहनों के लिए भी एक खास नियम तय किया है। नए नियम के बाद आप बिना HUID के गहने बेच नहीं पाएंगे। अगर आपने हॉलमार्किंग का नियम लागू होने से पहले सोने के जेवर बनवाए हैं और अब उसे बेचना या बदलवाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। पुरानी गोल्ड ज्वैलरी या दूसरे गोल्ड प्रॉडक्ट्स को बेचने से पहले आपको उन्हें भी हॉलमार्क्ड कराना होगा। गोल्ड की हॉलमार्किंग शुद्ध सोने की पहचान है। सोना कितना शुद्ध है ये हॉलमार्क देखकर आप पता कर सकते हैं। पुरानी ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग करवाने से आपको जहां आपके पुराने सोने के गहने की सही कीमत मिलेगी तो वहीं सरकार इस बात का भी पता लगा सकेंगी कि सोने में निवेश के जरिये कितना काला धन छिपाया गया है। सरकार ने इसी मकसद से 1 अप्रैल, 2023 से देश में सोने के सभी गहनों और गोल्ड प्रॉडक्ट्स पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID को अनिवार्य कर दिया है। इस यूनिक नंबर के जरिए सोने के गहने में सोने की शुद्धता के प्रतिशत की जानकारी मिलेगी। ज्वैलर्स आपको सोने की शुद्धता को लेकर बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। सोने की गहनों पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लोगो होगा। सोना 18 कैरेट का है, 20 कैरेट , 22 कैरेट या फिर 24 कैरेट का है उसकी डिटेल होगी।

इस रत्न को धारण करते ही लग जाएगी आपकी लॉटरी, घर बैठे कमाओगे करोड़ों

आम हो या खास हर इंसान के जीवन में पैसों का विशेष महत्व होता है। दिन-रात कड़ी मेहनत करके पैसा कमाया जाता है। वहीं, कुछ लोगों को घर बैठे बहुत कुछ मिल जाता है। हालांकि ऐसा कुछ ही खास भाग्यशाली लोगों के साथ होता है। अगर आपको मेहनत की दम पर ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो रही है तो आप भारतीय रत्न शास्त्र के अनुसार पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह लेना आवश्यक है। आइए जानते हैं रत्न शास्त्र के अनुसार पन्ना धारण करने की विधि और इसके फायदे और पन्ना किन लोगों के लिए पहनना शुभ होता है।

✍संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

क्या है पन्ना रत्न

भारतीय रत्न शास्त्र में हर रत्न के खासियत, उसे पहनने के फायदे और तरीकों के बारे में बताया गया है। हर ग्रह का कोई न कोई रत्न होता है। आज हम पन्ना रत्न के बारे में जानेंगे। ये बुध ग्रह का रत्न है, जिसे वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक माना गया है। किसी भी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और जीवन में खुशियां लाने के लिए पन्ना रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है।

पन्ना धारण करने के लाभ

- पन्ना पहनने से व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है।
- पन्ना पहनने से व्यक्ति में बुद्धि, तर्क, संवाद और धन बढ़ता है।
- अगर किसी जातक की कुंडली में बुध की अंतर्दशा चल रही है या बुध कमजोर है, तो उसे पन्ना धारण करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।
- बुध ग्रह को व्यापार का कारक माना गया है, इसलिए कारोबारियों के लिए ये बेहद शुभ फलदायी है।
- ज्योतिष के अनुसार पन्ना सही निर्णय लेने में मदद करता है।
- पन्ना धारण करने वालों पर बुध देव की कृपा हमेशा बनी रहती है।
- पन्ना धारण करने से बुध की कृपा से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं।
- पन्ना धारण करने से जुआ, सट्टा, लॉटरी के माध्यम से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं।

ये लोग धारण कर सकते हैं पन्ना

ज्योतिष के जानकारों के अनुसार पन्ना कन्या और मिथुन राशि के लोगों के लिए शुभ फलदायी होता है। कुंडली में बुध की महादशा होने पर या फिर बुध के 8वें या 12 वें स्थान पर होने पर भी व्यक्ति को पन्ना धारण करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष का कहना है कि किसी भी जातक की कुंडली में 6वें, 8वें और 12 वें भाव का स्वामी ग्रह बुध को तो ऐसे लोगों को पन्ना धारण करने से बचना चाहिए।

एक सुपारी बदल देगी आपका भाग्य, करियर के क्षेत्र में खुलेंगे सफलता के मार्ग

✍श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद
अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह-नक्षत्र का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल राशियों को शुभ-अशुभ फल देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रह-नक्षत्रों को शांत कराने के कई अचूक उपाय बताए गए हैं। आज ऐसे ही एक उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सुपारी से संबंधित है। शास्त्रों में सुपारी को गणेशजी का स्वरूप माना जाता है। पूजा की सुपारी पर जनेऊ चढ़ाकर जब पूजन किया जाता है तो अखंडित सुपारी गौरी-गणेश का रूप बन जाती है। शास्त्रों में पूजा की सुपारी से जुड़े कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जो हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं सुपारी के इन टोटकों के बारे में पूरी जानकारी।

सुपारी के उपाय

1.यदि आपका परिवार किसी प्रकार की आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो इसे दूर करने के लिए श्री गणेश पूजन करने के बाद एक लाल कपड़े में सुपारी को लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से जल्द छुटकारा मिलेगा और धन में बढ़ोतरी होती है।

2.सुपारी का टोटका नजरदोष दूर करने में बहुत मददगार माना जाता है। अगर घर के किसी भी सदस्य को नजर लग गई है तो सुपारी को 7 बार उस व्यक्ति के सिर से उतार कर हवन कुंड में जला दें। इससे बुरी नजर दूर होती है और आने वाली बलाएं टल जाती हैं।

3.यदि आप नौकरी को लेकर परेशान चल रहे हैं। समय पर नौकरी नहीं मिल रही है। व्यापार में कोई न कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करने के लिए शनिवार की रात पीपल के पेड़ की पूजा करें। पूजा करने के बाद एक सुपारी और एक रुपये का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन सुबह ही पीपल के पेड़ से एक पत्ते में इसी सुपारी और सिक्के को रखकर अपने धन स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है और करियर में प्रमोशन प्राप्त होता है।

4.यदि आप किसी विशेष काम से कहीं जा रहे हैं तो जाने से पहले एक कोरे लाल कपड़े में सुपारी और लौंग रखकर आप ओम गं गणपतए नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपके सारे काम सिद्ध और समय से पूरे होंगे।

5.बुधवार के दिन एक पान के पत्ते में देसी घी और लाल सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बनाएं, इसके बाद सुपारी को कलावे में लपेटें और उसे पान के पत्ते पर रखें। गणेश जी की पूजा के बाद इन सभी को एक लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें और इसकी पूजा करें। ऐसा करने से काम में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं।

25 मई को गुरु पुष्य सहित 5 शुभ योग, इन चीजों को खरीदने से भाग्य होगा प्रबल

ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन जो भी कार्य किया जाए उसमें निश्चित सफलता मिलती है। माना जाता है कि गुरु पुष्य योग के दौरान खरीदारी करने से सुख-समृद्धि, धन और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस बार 25 मई को गुरु पुष्य योग है, लेकिन बार यह बेहद खास हो गया है। दरअसल इस दिन प्रक्षा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। पुष्य योग के दिन जो भी शुभ कार्य करेगा, वह कई गुना बढ़ जाएगा। इस दिन विवाह को छोड़कर सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे नक्षत्रों में राजा कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति के पुष्य नक्षत्र में होने पर यह योग बनता है। 25 मई को गुरु पुष्य योग सूर्योदय से शाम 05.54 मिनट तक रहेगा।

गुरु पुष्य योग में इन चीजों का खरीदना शुभ

सोना

सोना सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गुरु पुष्य योग में खरीदा गया गोल्ड आपके धन और भाग्य में वृद्धि करेगा।

हल्दी

गुरु पुष्य योग में हल्दी खरीदना शुभ होता है। बृहस्पति का शुभ रंग पीला है और शुभता का प्रतीक भी है। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो हल्दी खरीदकर अपना भाग्य बढ़ा सकते हैं।

चना

गुरु पुष्य योग में आप सुख-समृद्धि को बढ़ाने के लिए चना भी खरीद सकते हैं। चने का इस्तेमाल पूजा में किया जाता। हल्दी और चने के अलावा पीला कपड़ा, पीतल और घी भी खरीद सकते हैं।

सिक्के

गुरु पुष्य योग के दिन सोने या चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। यह आपकी तरक्की में मदद करेगा।

मां लक्ष्मी की कृपा पाने प्रतिदिन अपनाएं ये उपाय

हर व्यक्ति को धन प्राप्ति की इच्छा रहती है। लेकिन धन और सुख-समृद्धि से परिपूर्ण वही व्यक्ति होता है, जिस पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धन की देवी मां लक्ष्मी चंचल होती हैं, वे एक जगह ज्यादा समय तक टिकती नहीं हैं। इसलिए मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करें, इसके लिए कुछ खास काम करना जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार कुछ उपाय प्रतिदिन करें, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और घर में सुख-समृद्धि भी बनी रहेगी।

तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप

ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर नियमित पूजा करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। घर की पूर्व उत्तर या फिर उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार और बुधवार का दिन छोड़कर तुलसी के पौधे को छुआ जाए, तो शरीर की शुद्धी होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। तुलसी के दर्शन से पापों से मुक्ति मिलती है।

नकारात्मक ऊर्जा का नाश

घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोबर के उपले पर लोबान और गूगल जलाकर इसका धुआं चारों कर करें। इसे घर और ऑफिस दोनों जगह किया जा सकता है। इस विधि को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्कता बनी रहती है। इसके साथ ही घर का वातावरण शुद्ध होता है।

दीपक लगाएं

माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक लगाएं। इसके साथ ही पेड़ की तीन परिक्रमा करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

सैलरी आने पर करें दान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर माह अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भगवान के मंदिर में दान करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा बनी रहती है।

✍श्री रोशनी शर्मा
9265235662
हस्त रेखा एवं फेस रीडर
(ज्योतिषाचार्य)

पहले नहीं किया तो अब करें सनस्क्रीन को दैनिक जीवन में शामिल- डॉ. धनोतिया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जीवन में ऐसे कई काम हैं जिसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने पर हम नहीं करते, मगर जागरूकता के बाद उसे दैनिक जीवन में शामिल करना फायदेमंद होता है। इसलिये यह कहावत बिल्कुल सटीक है, कि जब जागो तभी सवेरा। जी हां, यहां हम सनस्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से त्वचा संबंधी कई गंभीर बीमारी से भी बचा जा सकता है। इस महीने 27 मई को मनाए जा रहे राष्ट्रीय सनस्क्रीन माह के विशेष अवसर पर सनस्क्रीन के लाभ के बारे में बात करते हुए इंदौर स्थित त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका धनोतिया ने कहा कि सूर्य से निकलने वाली तेज हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इसलिये आवश्यक है कि रोजाना इस्तेमाल के लिये हम ऐसे उत्पाद का चयन करें जो त्वचा पर प्रतिदिन होने वाले खतरे से हमारी रक्षा करे। नियमित रूप से त्वचा के देखभाल में हमारे सौंदर्य प्रसाधनों में सनस्क्रीन की एक खास जगह होनी चाहिये। त्वचा संबंधी परेशानी जैसे- सनबर्न, झाईयां, मलीन त्वचा, फोटो एजिंग, त्वचा कैंसर, फोटोएलर्जिक प्रतिक्रियाओं, प्रकाश संवेदनशीलता रोगों और पोस्ट-इंफ्लेमेटरी हाइपरपिग्मेंटेशन की रोकथाम और प्रबंधन में सनस्क्रीन का उपयोग के संकेत मिलते हैं। दरअसल, सूर्य के सीधा संपर्क में आने से त्वचा पर असमान रंग होने लगता है। वहीं सनस्क्रीन का नियमित इस्तेमाल ऐसा होने से रोकता है। सनस्क्रीन का मुख्य उद्देश्य त्वचा को अल्प समय और लंबे समय तक चलने वाले त्वचा रोगों से बचाना है। सनस्क्रीन के फायदे जानने के बाद यह जानना सबसे जरूरी है कि एक अच्छे सनस्क्रीन का चयन कैसे करें। इस बारे में डॉ. प्रियंका धनोतिया कहती हैं कि ऐसे समस्क्रीन को चुनें, जो अल्ट्रा वॉयलेट ए(यूवीए) और अल्ट्रा वॉयलेट बी (यूवीबी) किरणों के खिलाफ विशाल स्पेक्ट्रम सुरक्षा प्रदान करता हो और जिसमें कम से कम 30 का सन प्रोटेक्शन फैक्टर(एसपीएफ) शामिल हो। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से त्वचा की देखभाल के लिये सनस्क्रीन को मॉइस्चराइजर के बाद और मेकअप से पहले लगाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में चीनी का बंपर प्रोडक्शन, महाराष्ट्र भी हो गया पीछे

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उत्तर प्रदेश अब चीनी उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है। इस राज्य ने 2022-23 के पेराई सत्र में चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र को भी पछाड़ दिया है। जबकि इस सत्र में राज्य में 118 चीनी मिलें काम कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में 210 चीनी मिलें काम कर रही थीं। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी मिल मामलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि जहां तक चीनी के उत्पादन की बात है तो उत्तर प्रदेश कई अन्य कारकों के साथ महाराष्ट्र से आगे है।

चौधरी ने आगे बताया कि चीनी सीजन 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल 107.29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। जिसमें 3.05 लाख टन खांडसारी (Khandsari) शामिल है। जबकि महाराष्ट्र में 105.30 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती 14.87 लाख हेक्टेयर में की जाती है। वहीं

उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का क्षेत्र 28.53 लाख हेक्टेयर है। यह भारत में सबसे ज्यादा है। पेराई का मौसम अक्टूबर से जून तक होता है। चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 2,348 लाख टन रहा, जबकि महाराष्ट्र में यह 1,413 लाख टन था। उन्होंने कहा कि 2022-23 के सत्र में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की ओर से कुल गन्ने की पेराई 1,084.57 लाख टन थी। जबकि महाराष्ट्र में यह 1,053 लाख टन रही। मंत्री ने आगे बताया कि सूबे में 19.84 लाख टन चीनी को एथनॉल (ethanol) में बदला गया है। जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 15.70 लाख टन था। दोनों राज्यों में स्थापित चीनी मिलों की संख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 246 चीनी मिलें स्थापित की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 157 है।

कई मिलों ने किसानों का किया भुगतान

उत्तर प्रदेश में 118 चीनी मिलें काम कर रही हैं। जबकि महाराष्ट्र में 210 चीनी मिलें काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि 2022-23 सत्र में किसानों को 28,494.32 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। प्रदेश की करीब 80 चीनी मिलों ने काम खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर किसानों को पूरे पैसे दे दिए हैं।

चौधरी ने कहा कि राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) निर्देशों और प्राथमिकताओं के तहत पिछले 6 साल में चीनी मिलों ने 2,11,700 करोड़ रुपये (किसानों को) का पेमेंट किया है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में 12 चीनी मिलें बेची गई हैं। जबकि 18 चीनी मिलें बंद थीं। उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य में BJP की सत्ता आने के बाद हमने नई मिलें खोली हैं। वहीं कुछ मिलों की क्षमता बढ़ाई गई है। पिछली सरकारों पर अपना हमला करते हुए चौधरी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के शासन (2007 से 2012 तक) के दौरान गन्ना किसानों को 93,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार (2012 से 2017 तक) में लगभग 95,215 करोड़ रुपये भुगतान किया गया था।

सयाजी इंदौर में दक्षिण भारत की अद्भुत पाककला का आनंद

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सयाजी इंदौर का क्रेविंग्स 18 से 28 मई 2023 तक मिस्टिकल टेल्स ऑफ साउथ फूड फेस्टिवल में प्रामाणिक और अद्भुत दक्षिण भारतीय व्यंजनों की एक रेंज पेश करेगा। मेहमान पोंगल, मसाला डोसा, पुलिहोरा, अप्पम, मेदु वड़ा, इडली साम्बर, थालास्सेरी बिरयानी, फिश करी, तवा ग्रिल्ड फिश, पाझमपोरी और अन्य व्यंजनों के साथ सांस्कृतिक उमंग में शामिल हो सकते हैं। स्वाद से भरपूर ये व्यंजन सुगंधित मसालों और पोषक तत्वों से भरे हुए हैं।

आयोजन के दौरान, सयाजी इंदौर के जनरल मैनेजर श्री अमित गेरा ने कहा कि 'दक्षिणी क्षेत्र की पहचान उनकी अपनी समृद्ध संस्कृति से बनती है। इस क्षेत्रों के व्यंजनों का स्वाद इनको खास और लोकप्रिय बनाता है, इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्रेविंग्स में पधारें तथा इस दावत का आनंद उठाएं।'

सयाजी इंदौर का क्रेविंग्स 24X7 खानपान की एक खास जगह है जिसमें नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज, एशियन और इटैलियन सहित अन्य व्यंजनों की व्यापक रेंज उपलब्ध है। विशाल और आरामदायक बैठने की जगह, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर माहौल आपके मूड को सेट करने के लिए एकदम उपयुक्त हैं।

मोबाइल सेक्टर में आएगी नई क्रांति. सरकार ने देशभर में लॉन्च की स्पेशल ट्रैकिंग सिस्टम

नई दिल्ली । आईपीटी नेटवर्क

सरकार इस सप्ताह एक निगरानी प्रणाली शुरू करने जा रही है। इस प्रणाली के जरिये देशभर में लोग अपने गायब या चोरी हो चुके मोबाइल फोन को 'ब्लॉक' कर सकेंगे या उसका पता लगा सकेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रौद्योगिकी विकास निकाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सीडॉट) दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कुछ दूरसंचार सर्किलों में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर प्रणाली को प्रायोगिक आधार पर चला रहा है। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अब इस प्रणाली को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया जा सकता है।

चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक कर सकेंगे लोग- उपाध्याय ने कहा, 'प्रणाली तैयार है और अब इसे इसी तिमाही में पूरे भारत में तैनात किया जाएगा। इससे लोग अपने खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक कर सकेंगे।' सीडॉट ने सभी दूरसंचार नेटवर्क पर क्लोन्ड मोबाइल फोन के इस्तेमाल का पता लगाने के लिए इसमें नई खूबियां जोड़ी हैं। सरकार ने भारत में मोबाइल उपकरणों की बिक्री से पहले इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई-15 अंक की संख्या) का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है।

मोबाइल नेटवर्क के पास होगी IMEI नंबरों की लिस्ट- मोबाइल नेटवर्क के पास मंजूर आईएमईआई नंबरों की सूची होगी, जिससे उनके नेटवर्क में अनधिकृत मोबाइल फोन के प्रवेश का पता लग सकेगा। दूरसंचार परिचालकों और सीईआईआर प्रणाली के पास उपकरण के आईएमईआई नंबर और उससे जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी होगी। कुछ राज्यों में इस सूचना का उपयोग सीईआईआर के जरिये गुम या चोरी गए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए किया जाएगा।

एडब्लूएस भारत में 1,05,600 करोड़ रु. का निवेश करेगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एमेजॉन वेब सर्विसेज ने भारत में 2030 तक क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में 1,05,600 करोड़ रु. का निवेश करने की अपनी योजना के बारे में बताया यह निवेश भारत में ग्राहकों द्वारा क्लाउड सर्विसेज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया जाएगा इस निवेश से 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1,94,700करोड़ रु. का योगदान मिलेगा। भारत में डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस योजनाबद्ध निवेश से हर साल भारतीय व्यवसायों में औसतन 1,31,700 फुलटाईम ईक्वैलेंट नौकरियों का निर्माण करने में मदद मिलेगी। ये नौकरियाँ भारत में डेटा सेंटर सप्लाई चेन के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, एवं अन्य क्षेत्रों में होंगी इस नए निवेश की घोषणा से पहले एडब्लूएस 2016 से 2022 के बीच 30,900करोड़ रु. का निवेश कर चुका है जिसके बाद भारत में 2030 तक एडब्लूएस का कुल निवेश बढ़कर 1,36,500 करोड़ रु. हो

जाएगा भारत में एडब्लूएस के निवेश का इन क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर रिपल इफेक्ट पड़ेगा तथा कार्यबल के विकास, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन के अवसरों, सामुदायिक संलग्नता और सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रमों का विकास होगा। एडब्लूएस इंडिया एवं साउथ एशिया में प्रेसिडेंट, कमर्शियल बिजनेस, पुनीत चंडोक ने कहा एडब्लूएस साल 2016 से भारत में क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए करोड़ों डॉलर्स का निवेश कर चुका है ताकि इस अपार वृद्धि में सहयोग मिल सके जो डिजिटल परिवर्तन के लिए क्लाउड के उपयोग में हमें देखने को मिल रही है उन्होंने कहा एडब्लूएस भारत में सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और स्थानीय ग्राहकों एवं साझेदारों को डिजिटल परिवर्तन लाने में मदद करने के अलावा हम 2017 से भारत में चालीस लाख से ज्यादा लोगों को क्लाउड का प्रशिक्षण दे चुके हैं, और 2025 तक अपना 100 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी का उद्देश्य पूरा करने के लिए छः यूटिलिटी-स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुके हैं। 2030 तक हमारा 1,05,600 करोड़ का योजनाबद्ध निवेश ज्यादा फायदेमंद रिपल इफेक्ट पैदा करेगा, और भारत को ग्लोबल डिजिटल पॉवरहाउस बनने की ओर ले जाने में मदद करेगा।''

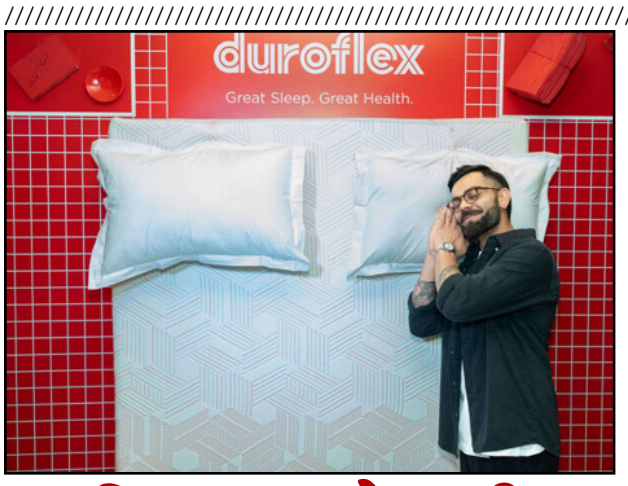

विराट कोहली बने ड्यूरोफ्लेक्स के ब्राण्ड एम्बेसेडर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के अग्रणी स्लीप सॉल्यूशंस प्रदाता ड्यूरोफ्लेक्स ने क्रिकेट आइकॉन विराट कोहली के साथ साझेदारी की है इस साझेदारी के तहत कंपनी लंबी और सेहतमंद जिंदगी को बढ़ावा देने में अच्छी गुणवत्ता की नींद के महत्व के बारे में बताने के अपने मिशन को आगे बढ़ाएगी विराट कोहली इस ब्राण्ड के मिशन के साथ मजबूती से जुड़े हैं और इसीलिये उन्होंने ड्यूरोफ्लेक्स के ब्राण्ड एम्बेसेडर की भूमिका की जिम्मेदारी स्वीकार की है यह दमदार गठबंधन संपूर्ण सेहत को बेहतर बनाने में अच्छी गुणवत्ता की नींद की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर होने वाली बातचीत को बदल देगा और इस संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। ड्यूरोफ्लेक्स के सीईओ मोहनराज जे. ने कहा स्लीप सॉल्यूशंस के बाजार में लंबी विरासत और अग्रणी स्थिति वाले ब्राण्ड के तौर पर, ड्यूरोफ्लेक्स में हम अच्छी नींद के महत्व को बढ़ावा देने के अपने मिशन को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिये प्रतिबद्ध हैं हमें विराट कोहली के साथ अपने गठजोड़ की घोषणा करने पर गर्व है क्योंकि वे नींद के महत्व पर हमारे जैसा जुनून रखते हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद के लिये वह एकदम परफेक्ट हैं अपने नये उत्पाद न्यूमा को लॉन्च कर हम बेहतर नींद लेने में भारत की मदद करने के अपने वादे को मजबूती कर रहे हैं ड्यूरोफ्लेक्स आगे की यात्रा के लिये रोमांचित है और अपने ग्राहकों को अभिनव तथा प्रभाशाली स्लीप सॉल्यूशंस देने और नींद की भूमिका पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।

प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए हुआ गठबंधन

ओप्पो इंडिया और तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप का संगारेड्डी जिले में

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अग्रणी ग्लोबल स्मार्ट डिवाइस ब्रांड, ओप्पो ने टी-एसआईजी (तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप) के साथ अपने गठबंधन की घोषणा की है। यह साझेदारी उड़ान परियोजना के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य तेलंगाना के संगारेड्डी जिले, हैदराबाद में ओडिया प्रवासी मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाना है। उड़ान द्वारा इन मजदूरों के स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की शिक्षा, भत्ता, और जीवन की परिस्थितियों सहित उनका जीवनस्तर सुधारकर उन्हें समर्थ बनाया जाता है। इस पहल के स्पॉन्सर के रूप में, ओप्पो, टी-एसआईजी और एड एट एक्शन (एनजीओ) के साथ उन 2500 से अधिक प्रवासी मजदूरों और 400 बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, जो पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जो अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 के बीच छः महीने तक संगारेड्डी जिले में रहेंगे।

उड़ान परियोजना में सात सरकारी विभाग मिलकर काम करेंगे, जिनमें जिला कलेक्टोरेट, श्रम विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग और संगारेड्डी जिला पुलिस शामिल हैं। वो मिलकर इन प्रयासों और पहलों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का निर्देशन टी-एसआईजी द्वारा श्री जयेश रंजन, आईएएस, प्रधान सचिव, उद्योग, वाणिज्य, आई एवं टी विभाग, तेलंगाना सरकार के मार्गदर्शन किया जाएगा।

इस साझेदारी के बारे में तसलीम आरिफ, वीपी एवं आरएंडडी हेड, ओप्पो इंडिया ने कहा, ''हमें संगारेड्डी जिले में उड़ान प्रवासी मजदूर परियोजना में सहयोग करने के लिए टी-एसआईजी के साथ गठबंधन करने की खुशी है। ओप्पो 'टेक्नॉलॉजी फॉर मैनकाईंड, काईंडनेस फॉर द वर्ल्ड' के अपने सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है, और यह साझेदारी हमारे सीएसआर के प्रयासों में एक बड़ा कदम है। टी-एसआईजी के साथ गठबंधन करके हमें 2500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को सशक्त बनाने और उनके स्वस्थ्य, शिक्षा, भत्ते एवं जीवन की परिस्थितियों को संबोधित कर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहयोग करने पर गर्व है। यह गठबंधन भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने और सस्टेनेबल विकास करने की ओप्पो की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है, और हम पूरे संगारेड्डी जिले में सकारात्मक एवं दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दृढ़निश्चित हैं।''

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।